पत्रांक–7/पद सृजन–15–02/2017सा0प्र0......................../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक.........................

विषयः– **माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 (क्रिमिनल) 1779/2016 में दिनांक 28.02.2017 को पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य के राईस मिलर्स के मामलों की सुनवाई हेतु 05 (पाँच) सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद सृजन कुल अनुमानित वार्षिक व्यय भार ₹ 50,43,912/– (पचास लाख तैंतालीस हजार नौ सौ बारह रू0 मात्र) की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–29253 दिनांक 29.04.2017 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 (क्रिमिनल) 1779/2016 में दिनांक 28.02.2017 को पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य के राईस मिलर्स के मामलों की सुनवाई हेतु 05 (पाँच) सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद सृजन की अनुशंसा की गयी थी।

2. उक्त अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत तदनुसार महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के उपर्युक्त पत्र एवं संलग्न व्यय विवरणी में अंकित पद संवर्ग के सम्मुख अंकित वेतनमान में ₹ 50,43,912/– (पचास लाख तैंतालीस हजार नौ सौ बारह रू0 मात्र) के वार्षिक तथा न्यायिक सेवा सवर्गों में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के अनुमानित व्यय भार पर गैर योजना मद में स्थायी रूप से 05 (पाँच) सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त सृजित किये जाने वाले पद का व्यय–बजट शीर्ष "2014 न्याय प्रशासन–लघु शीर्ष–105 सिविल और सेशन्स न्यायालय उपशीर्ष–0001 सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते मद से वहन किया जाएगा, जिसका विपत्र कोड सं0–"N–2014001050001" होगा एवं संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

4. इसमें प्रशासी पद वर्ग समिति की स्वीकृति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नकः–व्यय विवरणी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–7/पद सृजन–15–02/2017सा0प्र0 11385 /पटना–15, दिनांक 04/9/17

निबंधित

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 29.08.2017 में मद संख्या–04 के रूप में स्वीकृत के प्रसंग में/संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश/संबधित कोषागार पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ह0) 4/9/17
सरकार के अवर सचिव।

D/DRIVE/SEC-07/U.S. & D.S.

<u>व्यय–विवरणी</u>

संचिका संख्या–7/पद सृजन–15–02/2017

Statement of Anual Estimated Expenditure Chat

Sl. No.	Name of the Cadre	No. of Post	Pay Scale (P.S.) in Rupees	Average pay/ Basic pay (Upper Limit of P.S. + Lower Limit of P.S.)/2)	Annual Pay (Average Pay x Number of Post x 12)	Dearness Allowance @ 132%	Total Annual Estimated Expenditures (in Rupees)*
1	Civil Judge (Junior Division)	Five (05)	27700-770-33090-920-40450-1080-44770	36,235/-	21,74,100/-	28,69,812/-	50,43,912/-

कुल वार्षिक व्यय का योग – **₹ 50,43,912 /–** (पचास लाख तैतालीस हजार नौ सौ बारह रुपये) मात्र।

***नोटः– उपर्युक्त व्यय के अतिरिक्त समय–समय पर न्यायिक सेवा में नियमानुसार देय भत्ता भुगतेय होगा।

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

D/DRIVE/SEC-07/VYAY VIVARAN!